इस चिकित्सालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आधुनिक औषधि के लिए 550 बैड एवं "भारतीय औषधि" (पी० जी० आई०) के लिए 125 बैड क ग्रांट दिया गया है । उसी के अनुरूप इस अस्पताल में कर्मचारियों एवं चिकित्सकों की स्वीकृति है । इस समय चिकित्सालय में 950 बैड चलते हैं। कर्मचारियों का नितांत अभाव है । मरीजों की ठीक से देखभाल नहीं हो रही है । इस अस्पताल में गन्दगी भी बहुत है ।

पिछले वर्ष कई लाख रुपया खर्च करके मरीजों के कपड़े धोने के लिए एक बड़ी लान्ड्री मशीन यहां लगायी भी गयी । कर्मचारियों के अभाव में वह अभी तक बेकार पड़ी है । लाखों रुपया खर्च करके 6 लिफ्ट लगाई गई । आपरेटर के अभाव में वह बन्द हैं । दूर-दराज से मरीज आकर इधर उधर भटकते हैं। दलालों के चंगुल में पड़ते हैं । उनके परिवार के सदस्यों के साथ छेड़-छाड़, महिलाओं के साथ अनैतिकता की घटनायें बराबर होती हैं । खेद है कि इतने बड़े चिकित्सालय में कोई पूछताछ कार्यालय भी नहीं है ।

इस चिकित्सा विज्ञान संस्थान में क्लीनिकल साइड से हमेशा निदेशक होता रहा । उसका पूरा नियंत्रण दवाओं, डाक्टरों एवं कर्मचारियों पर था । लोग उससे डरते थे । रोगियों की अच्छी तर देखभाल होती थी । क्लीनिकल साइड के ही एक निदेशक स्वयं मरीज देखते थे । आपरेशन करते थे । इस अस्पताल की लोकप्रियता मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल तक थी । पर सीधे निदेशक की नियुक्ति अब प्रभावहीन हो गई है । इतना बड़ा चिकित्सा संस्थान इतने बड़े बजट के बावजूद भी बेकार हो गया है ।

आज लाखों मरीज परेशान व असहाय हैं । कर्मचारियों में असन्तोष है । प्रदेश के अन्य केन्द्रीय चिकित्सा संस्थानों के कर्मचारियों एवं यहां के कर्मचारियों के वेतन में भी असमानता है ।

अतः मैं आग्रह करूंगा कि शीघ्र स्वास्थ्य मंत्री जी इस ओर ध्यान दें । यह बहुत ही गंभीर मामला है वरना केन्द्रीय सरकार का इस संस्थान के ऊपर प्रतिवर्ष खर्च होने वाला करोड़ों रुपया बेकार साबित होगा ।

(ix) PAYMENTS OF REASONABLE PRICE TO SUGAR-CANE GROWERS IN RAJASTHAN.

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स राजस्थान के मेनेजमेंट को भारत सरकार ने अपने अधीन सन् 1978 से लिया हुआ है और इसके संचालन हेतु उस पर कस्टोडियन नियुक्त किया हुआ है । इस क्षेत्र में उत्पन्न गन्ने के शक्कर की रिकवरी, राजस्थान में अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक है । परन्तु, उक्त शूगर मिल्स से गन्ना उत्पादन को केवल 16 रुपए 10 पैसे प्रति क्विटल ही, गन्ने का मूल्य दिया जा रहा है, जब कि भारत के अन्य स्थानों पर 21 रु० प्रति क्विटल दिया जा रहा है, और उपरोक्त शूगर मिल्स पर भी गत वर्ष 21 रुपए प्रति क्विटल गन्ने का मूल्य उत्पादक को दिया गया था । इस क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों ने इस कम मूल्य दिए जाने के विरोध में आन्दोलन भी किया था व मिल्स पर गन्ना न पहुंचने के कारण कई दिनों तक मिल्स चालू नहीं हो सकी थी । बाद में गन्ने के मूल्य में बढ़ोत्तरी अनुदान के रूप में प्रति क्विटल देना स्वीकार किये जाने के बाद ही मिल चालू हो सका था । परन्तु अभी तक इस क्षेत्र के गन्ना उत्पादक को केवल 16 रुपए 10 पैसे प्रति क्विटल से ही मूल्य मिल द्वारा दिया जा रहा है, जो उसके साथ अन्याय है । अतः मैं खाद्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में सरकार की स्थिति स्पष्ट करें ।